

(c) The Government has not taken any decision on this matter so far.

(d) The Railwaymen have demanded payment of 8.33% of wages as minimum bonus.

(e) For railway employees alone the financial implications will be about Rs. 71 crores per annum.

(f) No such proposal has been received by the Government.

Amendment to Bonus Act

*77. SHRI ANANT DAVE:
SHRI DALPAT SINGH PARASTE:

Will the Minister of PARLIAMEN-TARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) Whether the recommendations of the Bonthalingam Committee have been considered and decision taken on an integrated policy of the Government on bonus issue as a whole;

(b) whether Government are contemplating to bring forward the necessary amendments in the Bonus Act framed on the basis of this decision;

(c) if so, what are its details; and

(d) if not, how it will affect the interest of industrial workers as such?

THE MINISTER OF PARLIAMEN-TARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) to (d). The question of bonus, including extension of the coverage and related issues, is receiving very careful consideration and the Government's intention is to introduce the necessary legislation before the festival season.

दो-मंजिले रेल डिब्बे

*78. श्री सुरेश्वर झा सुमन : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) दो मंजिले रेल डिब्बे बनाने के कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि थोड़ी दूर की रेल यात्रा में यात्रियों को भीड़ अधिक रहती है; और

(ग) क्या सरकार का दो-मंजिला रेल डिब्बे लगाने के मामले में थोड़ी दूरी की यात्रियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण):
(क) 1977-78 के दौरान सवारी डिब्बा कारखाने द्वारा बड़ी लाइन के 12 दो-मंजिले सवारी डिब्बों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है और 1979-80 की अवधि में 24 और दो मंजिले सवारी डिब्बों का उत्पादन होने की प्रत्याशा है।

(ख) जी हाँ, केवल महत्वपूर्ण स्टेशनों पर और उनके ग्राम पास।

(ग) अपेक्षाकृत कम धूल वाले थोड़ी दूरी के चुने हुए मार्गों पर दो मंजिले सवारी डिब्बे चलाने का विनिश्चय किया गया है।

Development of Cochin Port

*79. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision on schemes for the development of the Cochin Harbour submitted by the Port Trust; and

(b) if so, the details of the project and other details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) and (b). An integrated scheme for the development of Cochin Port for handling of POL and fertilisers at an estimated cost of Rs. 26.08 crores has been received from Cochin Port Trust for sanction by the Government. A decision would be taken on merits of the proposal.

पंजाब में काम करने वाले बिहार और उड़ीसा के बंधुओं मजदूर

*50. श्री राम नरेश कुमावाहा :

श्री राम सागर :

क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंधुओं मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई कानून बनाया था;

(ख) क्या सरकार का ध्यान "नवभारत टाइम्स" दिनांक 30 मई, 1979 में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि बिहार और उड़ीसा के लगभग 30 कृषि मजदूर जिला जालन्धर में तलवन्डी गांव में बंधुओं मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं और उनसे बन्धूक की नीक पर जबरवस्ती काम लिया जा रहा है;